भारत की राजनीति में गहरी हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़े

डॉ0 विनोद कुमार

एसो0 प्रोफे0, स्याना डिग्री कॉलिज, घनसूरपुर, जनपद– बुलन्दषहर।

सारांश

आज चारों तरफ सिर्फ मतलबी राजनीति है। राजनीति, कहीं वोट की तो कही नोट की, कहीं जाति की तो कहीं धर्म की, कहीं क्षेत्र की तो कहीं देश की, कही प्यार में राजनीति तो कही नफरत में राजनीति, कहीं दोस्ती में राजनीति तो कहीं दुश्मनी में राजनीति, कहीं गाँव की तो कहीं शहर की, कहीं अपनो की तो कहीं परायों की, पर कहीं न कहीं राजनीति तो हो रही है। कहने का तात्पर्य, राजनीति शब्द का क्षेत्र जितना व्यापक है उतना ही संकुचित भी। तभी तो एक बाप अपने बेटे से निःसंकोच यह कहता है, बेटा, अपने बाप से ही राजनीति कर रहे हो?

भारत जैसे देश में राजनीति शायद हर क्षेत्र में कामयाबी और रातोंरात अमीर बनने की कुंजी बन गई है. यही वजह है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा की तर्ज पर राजनीतिज्ञों की जमात लगातार लंबी होती जा रही है। सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए ? क्या उसे व्यवस्था के हाल पर छोड़ दिया जाए और यह माना जाए कि लोकतांत्रिक ताकतें और संस्थाएँ उससे एक दिन निपट लेंगी ? या आन्दोलन किया जाए ? आन्दोलन किसके नेतृत्व में चलाया जाए ? राजनीतिक दलों के नेतृत्व में या अराजनीतिक संगठनों के नेतृत्व में ? अगर वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और दलित, पिछड़ी जातियों के नेतृव वाले दल आन्दोलन न करें तो क्या किया जाए ? क्या साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी दलों के नेतृत्व में आन्दोलन का समर्थन किया जाए ? गैर–राजनीतिक संगठनों के आन्दोलन की सीमाएँ क्या हैं ? उन्हें कैसे बढ़ाया जाए या उन्हें दरकिनार कर दिया जाए ? क्या भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को नवउदारवादियों का नाटक मानकर उपेक्षित कर दिया जाए ? या उनके भीतर पनप रही व्यवस्था विरोध की चिनगारी को और कैसे आगे बढ़ाया जाए ?

मुख्य बिन्दु: *भारत, राजनीतिक, भ्रष्टाचार, संगठन, राजनेता, धर्म*

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 विनोद कुमार,
"भारत की राजनीति में गहरी हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़े",
RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 142-149
http://anubooks.com/?page_id=2004
Artcile No. 20(RP569)

प्रस्तावना

राजनीति एक सम्पूर्ण व्यवस्था कहलाती हैं, जिसका मूल उद्देश्य लोकहित होता हैं और जिसकी सफलता जनता की खुशहाली पर निर्भर करती हैं। राजनीति में जनता एक सेवक का चुनाव करती है ऐसा सेवक जिसे नेता कहा जाता है, जो जनता की हर समस्या से परिचित हो, उसके और जनता के मध्य कोई राज न हो। पारदर्शिता इस व्यवस्था का एक मूल अंग होता हैं। जब शासक अपने सहयोगियों के हर कार्य और राज से परिचित होता हैं तो वो सफल रहता हैं। लेकिन यह सभी बाते सिर्फ परिभाषित करने मात्र ही हैं, जिसका आज हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आज किसी भी नेता के लिए राजनीति का मतलब चुनाव जीत कर सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाना हैं और फिर 5 सालों तक जितना हो सके जनता के पैसे से अपना हित करना हैं। आज के नेता सेवक नहीं शक्ति में मदहोश अकुशल राजा बन गए हैं, जो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं।

आज चरों तरफ सिर्फ मतलबी राजनीति है। राजनीति, कहीं वोट की तो कही नोट की, कहीं जाति की तो कहीं धर्म की, कहीं क्षेत्र की तो कहीं देश की, कही प्यार में राजनीति तो कही नफरत में राजनीति, कहीं दोस्ती में राजनीति तो कहीं दुश्मनी में राजनीति, कहीं गाँव की तो कहीं शहर की, कहीं अपनो की तो कहीं परायों की, पर कहीं न कहीं राजनीति तो हो रही है। कहने का तात्पर्य, राजनीति शब्द का क्षेत्र जितना व्यापक है उतना ही संकुचित भी। तभी तो एक बाप अपने बेटे से निःसंकोच यह कहता है, बेटा, अपने बाप से ही राजनीति कर रहे हो? प्रदेश हो या देश, गाँव हो या शहर, घर हो या कार्यालय, चाय की दुकान हो या पान की, बस स्टैंड हो या रेलवे प्लेटफार्म, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया, खबरीलाल हो या वेब की दुनिया, इस समय चारों तरफ एक ही शब्द का जिक्र है राजनीति। यहाँ सुनने, देखने, और महसूस करने के साथ–साथ उठते–बैठते, जागते–सोते, यहाँ तक कि खाने और पीने में भी सिर्फ राजनीति है। जातिए क्षेत्र, भाषा इत्यादि, जब तक सामाजिक व्यवस्था का अंग था तब तक सब ठीक था। परन्तु अब यह राजनीतिक व्यवस्था का अंग होता जा रहा है तो भाई, यह उठक–बैठक क्यों? राजनीति न ही कोई आकाश से उतरी हुई कोई व्यवस्था है और न ही राजनेता आकाश से उतरे कोई राजदूत। यह राजनीति भी अपनी है और राजनेता भी हममे से कोई एक तो फिर यह एक दुसरे पर दोष कैसा लगाना? यह भी तो एक राजनीति ही हुई न! अब तो आलम यह हो गया है कि जहां भी राजनीति का जिक्र होता है वहां अपने आप भ्रष्टाचार भी मुंह खोल लेता है और यह स्पष्ट कर देता है की राजनीति और भ्रष्टाचार का तो चोली दामन का साथ हैं, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है।

भ्रष्टोचार भारत की शासन प्रणाली में इस हद तक समाया हुआ है कि आम आदमी का प्रत्येक प्रशासनिक कार्य से विश्वास उठ चुका है। व्यापक तौर पर फैल चुकी इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का इलाज केवल संपूर्ण तौर पर इस देश की राजनीति, जॉच व न्यायिक प्रणाली की कायापलट के द्वारा ही किया जा सकता है।

भारत जैसे देश में राजनीति शायद हर क्षेत्र में कामयाबी और रातोंरात अमीर बनने की कुंजी बन गई है. यही वजह है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा की तर्ज पर राजनीतिज्ञों की

जमात लगातार लंबी होती जा रही है। सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए ? क्या उसे व्यवस्था के हाल पर छोड़ दिया जाए और यह माना जाए कि लोकतांत्रिक ताकतें और संस्थाएँ उससे एक दिन निपट लेंगी ? या आन्दोलन किया जाए ? आन्दोलन किसके नेतृत्व में चलाया जाए ? राजनीतिक दलों के नेतृत्व में या अराजनीतिक संगठनों के नेतृत्व में ? अगर वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और दलित, पिछड़ी जातियों के नेतृव वाले दल आन्दोलन न करें तो क्या किया जाए ? क्या साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी दलों के नेतृत्व में आन्दोलन का समर्थन किया जाए ? गैर–राजनीतिक संगठनों के आन्दोलन की सीमाएँ क्या हैं ? उन्हें कैसे बढ़ाया जाए या उन्हें दरकिनार कर दिया जाए ? क्या भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को नवउदारवादियों का नाटक मानकर उपेक्षित कर दिया जाए ? या उनके भीतर पनप रही व्यवस्था विरोध की चिनगारी को और कैसे आगे बढ़ाया जाए ? क्या उसे एक नैतिक आन्दोलन का रूप दिया जाए या किसी संस्था का निर्माण कर सन्तुष्ट हो लिया जाए ? क्या इसे एकल मुद्दा आन्दोलन मानकर उससे सीमित सफलता की ही उपेक्षा की जाए ? और लोकतांत्रिक आन्दोलन का एक रूप माना जाए ? इन तमाम सवालों का जवाब सीधा नहीं है। न ही एकांगी जवाब है । पर इसका उत्तर निष्क्रियता तो कतई नहीं है। न ही इसका यह जवाब है कि अगर सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं होती तो इस तरह के आन्दोलनों का कोई मतलब नहीं है ।

यदि आज हम देष की सामाजिक स्थितियों के बारे में सवाल करें, कि महानुभव, वहां क्या हो रहा है? तो जानकारी मिलेगी कि आर्थिक एवं सामाजिक असमानतायें विस्फोटक हो रही हैं, जनअसंतोष बढ़ा है, घाटा दिखा कर मुनाफा कमाने के लिये निजी कम्पनियों को दी गयी छूट की वजह से न सिर्फ खनिज तेलों की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बेलगाम घोड़ा बन गयी है। देश की सामाजिक संरचना टूट रही है। हम बाजार में खड़े हैं, और आम जनता की जेब खाली है। सरकार की सामाजिक विकास योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। अब सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों से हाथ खींचती जा रही है।

यदि आज हम देश की राजनीतिक संरचना के बारे में सवाल करें, तो पता चलेगा कि उदारीकरण हर एक राजनीतिक दल का अनिवार्य मुददा है। जनतंत्र संकटग्रस्त है। सरकार भ्रष्ट है, विपक्ष भ्रष्ट है, मंत्रालय से लेकर प्रशासनिक विभागों की हालत खराब है। विचारहीन राजनीति ने अनास्था और अविश्वास को लोगों में भर दिया है। मौजूदा समाज व्यवस्था संकटग्रस्त हैं, उसके हर एक अंग से सड़ांध की बू आ रही है।

पिछले एक दशक ने जनतंत्र की राजनीतिक संरचना की बुनावट को बदल दिया है। जनतंत्र का ढांचा खड़ा है, मगर उस पर वित्तीय एकाधिकारवादी ताकतों की पकड़ मजबूत हो गयी है। उन्होंने एक ऐसे तंत्र को विकसित कर लिया है, जहां आम जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। यदि राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करें, तो वह सुविधा शुल्क है। यूरोपीय देश और अमेरिका में जिसे वैधानिक स्वीकृति मिली हुई है। जो जहां है, वहीं कमाई कर लेता है। पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुष कई तेल कम्पनियों के महत्वपूर्ण शेयर होल्डर हैं। राजनीति अब एक पेशा है।

मौजूदा हालात में कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। वह चाहे कांग्रेस के नेता, मंत्री और सांसद हों या फिर भाजपा या दूसरे राजनीतिक दलों के. भारत जैसे देश में यह आम धारणा बन गई है कि एक बार सांसद बन जाने पर कम से कम सात पुश्तों के खाने–पीने का इंतजाम हो जाता है. इसलिए इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग की तमाम पाबंदियों और चुनावी आचार संहिता के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में करोड़ों का खेल होता है। तमाम लोग इस भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं से अवगत होने के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। असली राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरूआत तो यहीं से होती है। तमाम दलों पर मोटे पैसे के एवज में टिकट बेचने के आरोप भी अब आम हो गए हैं। अब जो व्यक्ति पहले मोटी रकम देकर टिकट खरीदेगा और फिर करोड़ों की रकम फूंक कर चुनाव जीतेगा, वह सत्ता में पहुंच कर तो अपनी रकम तो सूद समेत वसूल करने का प्रयास करेगा ही।

बड़े राजनीतिक दलों की बात छोड़ भी दें, तो छोटे और क्षेत्रीय दल भी कम से कम राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद तो चारा घोटाले में जेल की हवा तक खा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जैसी पार्टियों के नेता तो सिर से पांव तक इस भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वहां मंत्री पर पत्रकार को जला कर मार देने का आरोप लगता है। लेकिन पैसों के बूते पर उसे भी मैनेज कर लिया जाता है। तमाम दलों में ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराध के दर्जनों मामले लंबित हैं। कार्यपालिका की बात छोड़ दें तो अब न्यायपालिका के दामन पर भी भ्रष्टाचार के धब्बे नजर आने लगे हैं। इस आरोप में अब तक विभिन्न अदालतों के कई जज भी बर्खास्त किए जा चुके हैं।

एक मामूली नगरपालिका पार्षद से लेकर देश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर रहने वाले लोगों पर भी अक्सर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते रहे हैं। कांग्रेसी मिल्कियत वाले अखबार नेशनल हेराल्ड और इसके शेयरों के ट्रांसफर का मामला तो एक मिसाल भर है। इस अखबार के मालिकाने के रहस्यमय तरीके से बदलाव ने देश पर कोई छह दशकों तक राज करने वाले नेहरू परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 साल में देश की जो प्रगति होनी चाहिए थी, नहीं हो पायी। कहते हैं कि इसके पीछे भ्रष्टाचार की गुलामी सबसे बड़ी वजह है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रश्टाचार के दलदल में धंसता नजर आने लगा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि 21 दिसम्बर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। डॉ. लोहिया के इस वक्तव्य के पांच दशक से अधिक समय हो चुके हैं और इन पांच दशकों में देश में भ्रष्टाचार की जकड़न लगातार बढ़ी है। और यही वजह है कि आज 18 हजार से अधिक गांवों में बिजली नहीं पहुंची है और लोग अंधेरे की गुलामी झेल रहे हैं।

बात देश में उग्रवाद के बढ़ने की करें, बात गरीबी के मकड़जाल की करें, बात बेतहाशा

बढ़ती महंगाई डायन की करें, बात अपराध की करें, बात महिला सशक्तिकरण की करें, बात बेरोजगारी की करें तो इस सबके पीछे लगातार क्षीण होती राजनीतिक इच्छाशक्ति और भ्रष्टाचार की विकरालता सबसे अहम वजहें हैं। सियासत और भ्रष्टाचार का यह गठजोड़ आज ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जिसने 68 साल पहले मिली आजादी के सारे मायने ही बदल दिए हैं।

विभिन्न संगठनों के संघर्ष के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को देषभर में सूचना का अधिकार कानून भी लागू किया गया। इसके बावजूद रिश्वत खोरी कम नहीं हुई। अफसोस तो इस बात का है कि भ्रष्टाचारी गरीबों, बुजुर्गों और विकलांगों तक से रिश्वत मांगने से बाज नहीं आते. वृद्धावस्था पेंशन के मामले में भी भ्रष्ट अधिकारी लाचार बुजुर्गों के आगे भी रिष्वत के लिए हाथ फैला देते हैं।

भारत दुनिया के तेज आर्थिक विकास वाले देशों में है, पर इस विकास का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। इसका असर उसके विकास पर भी पड़ा, जो पिछले महीनों में लगातार धीमा हुआ है। सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं और गरीबी बढ़ रही है। भारत ने 90 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे। सुधारों से उम्मीद थी कि लोगों के आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देने की वजह से गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और लैंगिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं। अब यह देश के विकास को प्रभावित कर रहा है। दो दशक के आर्थिक सुधारों की वजह से देश ने तरक्की तो की है, लेकिन एक तिहाई आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। भारत इस अवधि में ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया भर के एक तिहाई गरीब रहते हैं।

भारत सरकार 2012 से 2017 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर एक खरब डॉलर खर्च करेगी। इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बड़ी भागीदारी होगी। लगभग 30 फीसदी खर्च पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिये जुटाया जाएगा। देश के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरक्की का बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का स्तर भी ज्यादा होता है। इसकी वजहें हैं।

इन परियोजनाओं के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के दौरान बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी होती है। वर्ष 2010 में केपीएमजी के धोखाधड़ी से जुड़े सर्वे में इस सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियों ने कहा कि रिश्वत देने का अहम मकसद प्रशासनिक अनुमति लेना रहा। दरअसल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को खोल देने से इसमें निवेश करने वालों की भीड़ लग गई है। हर कोई इसमें हिस्सेदारी चाहती है। कई अनुभव कंपनियां भी इस सेक्टर में कूद पड़ी हैं। अब परियोजनाएं कम हैं और इसमें निवेश करने वाले ज्यादा। ऐसे में रिश्वत के जरिये परियोजना हथियाने वालों की तादाद बढ़ गई है। भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह परियोजनाओं के ठेक हासिल करने की जटिल प्रक्रिया। पर्यावरण क्लीयरेंस, मल्टीपल वेंडर एग्रीमेंट और नियामक एजेंसियों के मानक पर खरा उतरने की जरूरत की वजह से यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा संसद में पेश करने के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2004–2011 की अवधि में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी,

कोयला खण्डों का आवंटन नीलामी के बिना ही किया गया था जिसकी बदौलत कुछ कंपनियों ने इन कोयला खण्ड़ों को बहुत सस्ते दाम में खरीद लिया था। कैग द्वारा किए गए मूल्यांकन से इस बात का पता चला कि इस तरह नीलामी करने से देश की सरकार को 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 176 देषों की सूची में भारत 94वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार विरोधी अंतरराष्ट्रीय संस्था की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रिश्तखोरी का स्तर काफी ऊंचा है। भारत में 70 फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले दो साल में भ्रष्टाचार की स्थिति और बिगड़ी है। पिछले साल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में विशाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, लेकिन जन लोकपाल बनाने की मांग को राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन नहीं मिला। पार्टियां अपने को आरटीआई कानून से भी अलग रखना चाहती हैं।

भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का कहना है कि भारत का 2011 से 2012 के बीच भ्रष्टाचार के कारण सात अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2जी टेलीकॉम, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला घोटालों से हुए नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो हजारों करोड़ के हैं। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था के विकास पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है और जर्मनी जैसे देशों की विदेशी कंपनियों ने तो इस पर अब खुलेआम अपनी चिंताएं जतानी शुरू कर दी हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कंपीटीटिवनेस इंडेक्स–2010 के मुताबिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे इसलिए व्यापार, कारोबार, राजकोषीय और सरकारी खर्च में खुलेपन के साथ–साथ भ्रष्टाचार से मुक्त माहौल भी जरूरी है। भ्रष्टाचार भारत की विकास की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बिजनेस कंस्ल्टेंसी कंपनी केपीएमजी ने हाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े अपने हाल के सर्वे में कंपनियों के सीईओ, चेयरमैन, कंपनी सेक्र टेरियों, मैनेजरों और कानूनी सलाहकारों को शामिल किया है।

गौरतलब है कि जर्मनी के बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत में काम कराने के लिए 54 फीसदी लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। जबकि पूरी दुनिया की चौथाई आबादी घूस देने को मजबूर है। इस संगठन एनजीओ ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में दुनियाभर के 86 देशों में 91 हजार लोगों से बात करके रिष्वतखोरी से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं। 2010 के ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के मुताबिक पिछले 12 महीनों में हर चौथे आदमी ने 9 संस्थानों में से एक में काम करवाने के लिए रिश्वत दी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग से लेकर अदालतें तक शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में अफगानिस्तान, नाइजीरिया इराक और भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देषों की फेहरिस्त में शामिल किये गए हैं। इन देशों में आधे से ज्यादा लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 74 फीसदी लोगों का कहना है कि देश में पिछले तीन बरसों में रिश्वतखोरी में खासा इजाफा हुआ है, बाकी दुनियाभर के 60 फीसदी लोग

ही ऐसा मानते हैं। इस रिपोर्ट पुलिस विभाग को सबसे ज्यादा भ्रष्ट करार दिया गया है। पुलिस से जुड़े 29 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी है। संस्था के वरिष्ठ अधिकारी रॉबिन होंडेस का कहना है कि यह तादाद पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और 2006 के मुकाबले दोगुनी हो गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन (79वें), भारत (84वें), पाकिस्तान और बांग्लादेश (139वें) में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। हालत यह है कि धार्मिक संगठनों में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल 2003 से हर साल भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। वर्ष 2009 की रिपोर्ट में सोमालिया को सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है, जबकि इस साल भारत इस स्थान रहा है। देश में पिछले छह महीनों में आदर्श हाउसिंग घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों में धांधली, और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। जब ऊपरी स्तर पर यह हाल है तो जमीनी स्तर पर क्या होता होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। टीआई की रिपोर्ट में न्यूजीलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन और स्विटजरलैंड को दुनिया के सबसे ज्यादा साफ–सुथरे देश बताया गया है। गौरतलब है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय बर्लिन में स्थित है और दुनियाभर के 90 देशों में इसके राष्ट्रीय केंद्र हैं। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का स्तर मापने के लिए टीआई दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंक्स, संस्थाओं और निर्णय श्रमता में दक्ष लोगों की मदद लेता है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर जारी की जाती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 191 देशो की फेहरिस्त में भारत को 178वें स्थान पर रखा गया था। करेप्शन प्रेसेप्शन इंडेक्स में भारत 87 वें पायदान पर है। संसद में बैठे नेताओं में से करीब एक चौथाई पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। 1948 से 2008 तक अवैध तरीके से हमारे देश से करीब 20 लाख करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं, जो देश की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) का चालीस फीसदी है।

सर्वे मे 90 फीसदी लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार की वजह से शेयर बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ता है। लगभग 40 फीसदी लोगों ने माना कि बाजार के उतार–चढ़ाव में इसकी भूमिका होती है। सर्वे के मुताबिक 32 फीसदी का मानना था कि भ्रष्टाचार संस्थागत निवेशकों को दीर्घावधि के निवेश से रोकता है। वाशिंगटन स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल इंटग्रिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से टैक्स चोरी, अपराध और भ्रष्टाचार के जरिये 1948 से लेकर 2008 तक यानि 60 साल में 462 अरब डॉलर देश से बाहर ले जाया जा चुका है।

आज पूरे भारत की जनता भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। इसके विरुद्ध भारत के एक समाज–सेवक, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन भी चलाया था। उनके आह्वान पर लाखों लोग देश की सड़कों पर उतर आए थे। ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के आगे सरकार झुक जाएगी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए कानून बनाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस सिलसिले में **सेर्गेय तोमिन** ने कहा–

अन्ना हजारे के आंदोलन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ अन्य आंदोलनों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है? पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं है। इसे एक ही झटके में दूर नहीं किया जा सकता है।दूसरी बात यह है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें देश की राजनीतिक प्रणाली और प्रशासन प्रणाली में गहराई हुई हैं।

पूरी प्रणाली ही गड़बड़ाई हुई है। भ्रष्टाचार को कुछ महीनों और यहाँ तक कि कुछ सालो में भी खत्म नहीं किया जा सकता है।कड़ी सजा, भारी जुर्माने और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के स्टैंड से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। चीन में भ्रष्टाचार के मामले में हर्जाने और जुर्माने की राशि काफी बड़ी है। साथ ही भ्रष्टाचार के दोषियों को मौत की सजा भी मिल सकती है। चीन के कानून में सरकारी अधिकारियों को अपनी आय और संपत्ति को सार्वजनिक करना जरूरी है।

भारत में भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है। राजनेता अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप दाग रहे हैं। ऐसा करते हुए वे अपने–अपने दलों के लिए राजनीतिक लाभ हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। इस बीच, भारतीय समाज के लगभग सभी वर्ग भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति की चक्की में पिस रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए था, वे आज भी बाहर खुलेआम मौज कर रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- *देवी, महाश्वेता और त्रिपाठी, अरुण कुमार ''भ्रष्टाचार और अन्ना आन्दोलन '' वाणी प्रकाशन 20 जुलाई 2012, पृ0– 35।*
- *आज की आवाज टीम ''भारत में राजनीति और भ्रष्टाचार '' December 16, 2013, पृ0– 18*
- *गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) की एक रिपोर्ट बर्लिन, जर्मनी, पृ0– 4*
- *बेदी, किरण '' भ्रष्टाचार भारत छोड़ो '' प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2015, पृ0– 102 ।*
- *वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कंपीटीटिवनेस इंडेक्स – 2010 की एक रिपोर्ट, पृ0– 58*
- *http://samajikbhrstachar.blogspot.in/*
- *http://hindi.sputniknews.com/hindi.ruvr.ru/2013_12_04/254477742/*